[Shri L. B. Shastri]

जी के इन सब बातों के कहने के बावजूद भी मैं चाहता हूं कि आप मेहरबानी कर के एक एक्सपर्ट कमिटी (विशेषज्ञ समिति) बनाये और उसके मेम्बरों पर भरोसा रखिये, उस की सद्भावना पर विश्वास कीजिये । उनका उद्देश्य यह हर्गिज नहीं होगा कि रेलवे की व्यवस्था में गड़बड़ पड़ जाये और इससे आपको कोई हानि नहीं होगी । कमिटी न बना कर आप समस्या पर अकेले ही दिमाग लड़ायेंगे और मैं समझता हूं कि इससे कहीं बेहतर यह होगा कि ज्यादा लोग समस्या पर विचार करें और जो हल वह सुझायेंगे वहां कहीं अच्छा होगा । इस लिये मैं अब भी कहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर जिद्द न करें, जो कुछ मैं ने कहा है उसको ध्यान में रखते हुये इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें । मेरा पक्का विश्वास है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने से किसी किस्म की रेलवे की व्यवस्था में अड़चन नहीं पड़ेगी । क्योंकि दूसरा प्रस्ताव पेश होने वाला है इस लिये मैं और ज्यादा न कहते हुये इतना ही कहना चाहता हूं कि वह इसे ज़रूर स्वीकार कर लें ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : आप इसे विदड्रा (वापस) नहीं करते ।

Mr. Chairman: I shall put the resolution to the House.

The question is:

> "This House is of opinion that a Committee consisting of Members of Parliament and experts be appointed at an early date—
>
> (1) to examine the whole question of regrouping of Railways and to recommend to the Government measures for improving the administrative effciency of the Railways; and
>
> (2) to consider the proposals for the expansion of railway transport in order to meet the increased demand on it during the Second Five Year Plan".

The motion was negatived.

RESOLUTION *RE.* INDUSTRIAL SERVICE COMMISSION

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर) : सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी और श्री राजा राम शास्त्री को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ज्यादा न बोल कर और दूसरे मेम्बरों ने जो कि इस प्रस्ताव पर जो कि अभी हाउस के सामने पेश था बोलना चाहते थे, न बोल कर, मुझे यह मौका दिया कि मैं अपने प्रस्ताव को यहां पर पेश कर सकूं । इससे पूर्व कि मैं और कुछ कहूं मैं चाहता हूं कि पहले अपने प्रस्ताव को हाउस के सामने प्रस्तुत कर दूं । मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

> "इस सभा की यह राय है कि सरकारी कारखानों, उद्योगों और अन्य संस्थाओं के लिये योग्य और उपयुक्त व्यक्ति भर्ती करने के लिये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (संघ लोक सेवा आयोग) की तरह एक औद्योगिक सेवा कमीशन स्थापित किया जाय ।"

यह प्रस्ताव जैसा कि इसके शब्दों से प्रकट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है । हमारे देश में औद्योगीकरण की जो प्रगति हो रही है वह इतनी विशाल है और इतनी महत्वपूर्ण है कि इस प्रश्न पर ठंडे होकर बैठे रहना और गड़बड़ी पड़ने का मौका देना उचित नहीं है । आज हमारे देश में राज्य सरकारों की ओर से जो कारखाने और उद्योग चलाये जा रहे हैं उनमें दो हजार करोड़ से भी ज्यादा की रकम लगी हुई है और जब उन उद्योग धंधों की ओर हम देखते हैं वहां पर अव्यवस्था और गड़बड़ी ही पाते हैं और इसका एक मुख्य कारण लोगों में दक्षता की कमी है । यही कारण है कि प्रगति धीमी है । मैं कई उदाहरण दे सकता हूं कि जहां जहां भी कारखाने

खुले हैं वहां बड़े बड़े स्कैंडल्ज़ (गड़बड़) होने की घटनायें हुई हैं । आपको मालूम है कि हिदुस्तान हाउसिंग फैक्टरी (हिन्दुस्तान भवन निर्माण कारखाना) किस तरह से शुरू हुई और उसका इन्तज़ाम समय समय पर बदलता गया और आज उसकी क्या अवस्था है । हमारे उत्पादन मंत्री जानते हैं कि उनको उस फैक्टरी को छोड़कर मिनिस्टरी आफ वर्क्स हाउसिंग एण्ड सप्लाई (निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय) के सुपुर्द करना पड़ा है आपको मालूम ही है कि अभी पिछली बार अम्बरनाथ मशीन टूल फैक्टरी के सम्बन्ध में ही यहां पर वादविवाद हुआ था और वहां पर कितनी दुर्व्यवस्था रही और उत्पादन समय पर शुरू नहीं हो सका । बंगलौर में जो कारखाने खुले हैं और जिसमें टैलीफून इंडस्ट्रीज़ (टेलीफोन उद्योग) एक है वहां पर आप ने देखा होगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने रिश्तेदारों को रख कर गड़बड़ी पैदा की और काम की प्रगति में बाधा डाली । जो प्रस्ताव मैं ने पेश किया है उस पर बड़े ध्यान से गौर करने की आवश्यकता है और इसको मानकर सरकार का जो उद्देश्य उद्योग धंधों को चलाने का है वह पूरा हो सकता है । हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में उत्पादन बढ़े और कारखानों का इन्तज़ाम दक्ष लोगों के हाथ में हो । मैं पूछता हूं कि क्या कारण है कि आज जो सरकार उद्योग चलाती है वह सफल क्यों नहीं होते हैं और क्या कारण है कि उनके मुकाबले में निजी उद्योग धंधे सफलता पूर्वक चलते हैं । यह जो निजी उद्योग धंधों और सरकारी उद्योग धंधों में अन्तर है इसका क्या कारण है...

Shri U. R. Bogawat (Ahmednagar South): Bureaucratic sector.

श्री एम० एल० द्विवेदी : तो यह निश्चित है कि हमारे उद्योगों में जो लोग रखे जाते हैं वह अपना काम ठीक तरह से नहीं करते हैं और उनमें भ्रष्टाचारी व्यक्ति रख लिये जाते हैं । इस वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि हमारे उद्योग धंधों का नवीनीकरण हो और उनमें दक्ष और योग्य व्यक्ति भरती किये जायें । यदि ऐसा नहीं होता है तो इन उद्योग धंधों का बहुत बुरा हाल होगा और हमारी सरकार को असफलता का सामना करना पड़ेगा.....

Mr. Chairman: Order, order, The House stands adjourned till 11-0 A.M. on Monday.

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, the 28th November, 1955.